सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

कानपुर, शनिवार, 13 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 331, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड सांसद रमेश अवस्थी के समधी के यहां आयकर विभाग... Pg03

Pg12

आतंकी हमलाः पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत सांसदों ने किया शहीदों को नमन

निर्विरोध चुने जाएंगे, कल होगी औपचारिक घोषणा

पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नये अध्यक्ष!

केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 में अखिलेश यादव को रोकने के साथ सीएम योगी को भी घेरने की कोशिश की!

» अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया।

लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिये पंकज चौधरी का नाम आगे कर केंद्र ने 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए को कड़ी टक्कर देने के साथ योगी की घेराबंदी का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिये जब से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम चर्चा में आया तब से यूपी में खास कर पूर्वांचल में की राजनीति में माहौल गर्म हो गया है। जले, कटे, सिर दर्द, बदन दर्द के तेल निर्माता से राजनीतिज्ञ बने पुराने धनाढ्य पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्वांचल में अपने जाति के बड़े नेता हैं। 1991 से एक चुनाव 2004 का छोड़ कर वह लगातार महराजगंज से सांसद चुने जा रहे हैं।

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का संकेत देकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती पेश कर दिया बल्कि ज्वलंत हिंदुत्व के ब्रांड अम्बेसडर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ में ही घेरने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिये अब तक जितने भी प्रयोग किये गये ये उनमें सबसे मास्टर स्ट्रोक है। फिलहाल यह भाजपा है अंतिम निर्णय आने के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। योगी के घेरेबंदी की पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। लेकिन हर बार केन्द्री पटाखा फुस्स हो जाता था। जानकर इसे योगी आदित्यनाथ के निर्विघ्न उड़ान में बाधा मान रहे हैं।

11 मई 2025 को गोरखपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन था। दूसरे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया। बताते हैं कि मुख्यमंत्री उस दिन गोरखपुर में थे, लेकिन वह इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। इन तीनों नेताओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घनिष्ठता कम है। लेकिन तीनों एक साथ हैं।

भाजपा के जानकार कहते हैं कि नेताओं की मंशा के अनुसार जो खबर आ रही है यदि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो यूपी में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को सजग हो जाना चाहिये। अब उन्हें पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अखिलेश यादव के पीडीए से लड़ने के लिये यह अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन यदि यह निर्णय बैक फायर किया तो घर में स्थित तनावपूर्ण हो जायेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि यूपी में भाजपा का सपा से पिछड़ने का नेतृत्व ऐसा रास्ता निकलेगा जो राह कम रार को ज्यादा हवा दे सकती है। यह निर्णय योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर जिले, मंडल और पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को कमजोर करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वह आपसी मधुरता नहीं है, वर्तमान में जिसकी दरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वस्त महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के घर 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के पहुंच गये थे। तब बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के 200 मीटर पैदल चल कर पैदल ही पंकज चौधरी के घर पहुंच गये थे।

बहरहाल, प्रदेश मुख्यालय में नामांकन आज दोपहर दो बजे से तीन बजे के बीच होगा। शाम तक नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी का समय है। उम्मीद एक ही नेता के नामांकन करने की हो रही है। रेस में सबसे आगे केंद्रीय मंत्री व सात बार के सांसद पंकज चौधरी चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की औपचारिक घोषणा रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी व मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा कार्यालय पहुंच गई हैं। इस तरह के कयास लग रहे हैं कि इस बार बीजेपी किसी महिला को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है।

पंकज चौधरी के प्रस्तावक

पंकज चौधरी के प्रस्तावकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना व बेबी रानी मौर्य हैं।

अभिषेक गुप्ता हत्याकांडः जब्ती के लिए संपत्तियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरु

महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे पर गैंगस्टर

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

अलीगढ़। महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने के बाद चर्चा में आने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर शिकंजा कस गया है। पूजा के पति अशोक पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है। इनका गैंग भी यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने पंजीकृत किया है। इसे नया नाम डी-223 दिया गया है। महामंडलेश्वर के पति अशोक पांडेय को गैंग का सरगना बनाया है। इसी के साथ जब्ती के लिए इनकी संपत्तियों को चिह्नित करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूरा एक्शन टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में अलीगढ़ पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल करने के बाद किया गया है।

टीवीएस शोरूम मालिक की हत्या 26 सितंबर की रात खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें नामजद अशोक पांडेय को पुलिस ने पहले ही दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद दोनों शूटर पकड़े गए। पूजा शकुन पांडेय को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही अभिषेक के खैर में टीवीएस के शोरूम में पार्टनरशिप चाहती थी। अभिषेक के मना करने पर पूजा ने उसे फंसाने के लिए साजिश रची। वहां कामयाबी नहीं मिली तो अपने घर पर काम करने वाले मिस्त्री व उसके सहयोगी से हत्या करा दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ 33 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि अशोक पर कुल सात व पूजा पर पांच मुकदमे दर्ज हैं। शूटर आसिफ पर भी चार मुकदमे हैं। इस आधार पर इनका गैंग पंजीकृत किया गया है।

शूटरों की जमानत हो चुकी है रद्द

चारों आरोपी जेल में हैं। पूजा व अशोक को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं, कोर्ट में ट्रायल की तैयारी है। पूर्व में दोनों शूटरों की जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। अशोक की ओर से भी जमानत डाली गई है, जिस पर सुनवाई होगी।

जिले में छह नए गैंग पंजीकृत

जिले में छह और गैंग पंजीकृत किए गए हैं। इनमें गांधीपार्क थाने में चोरी के आरोपी बबलू पठान समेत दो लोग, रोरावर थाने में हत्या में आरोपी जैद उर्फ कंजा समेत छह लोग, हरदुआगंज में लूट में सुमित समेत दो लोग, दादों में लूट के आरोपी देवेंद्र समेत चार लोग, टप्पल में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी धर्मवीर समेत तीन लोग, इगलास में तस्करी में शामिल कोमल समेत दो लोगों का गैंग शामिल है।

एसआईआर : राजनीतिक दलों से संवाद और मतदाता सूचियों का सटीक मिलान किया जाए

» एसआईआर अभियान की प्रगति पर केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा

» अफसरों को पारदर्शिता, समयबद्धता और डिजिटाइजेशन बढ़ाने पर दिया जोर

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रगति को लेकर शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) से अभियान की स्थिति पर विस्तार से सवाल-जवाब किए गए। केंद्रीय

निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिया कि एसआईआर अभियान की प्रत्येक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता मैपिंग और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान राजनीतिक दलों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए और उन्हें समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। विशेष रूप से जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति न बने। जिले में चल रहे डिजिटाइजेशन कार्य पर संतोष जताते हुए निर्वाचन आयुक्त ने नो-मैपिंग की समस्या को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने बूथ स्तर पर बीएलओ और बीएलए के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया, जिससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके।निर्वाचन आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, उनके माता-पिता और स्वजन से संबंधित विवरणों का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से विधिवत मिलान किया जाए। इससे अपूर्ण मैपिंग की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।मतदाता शिकायतों के निस्तारण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि जिन्हें अब तक गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है या जो किसी भी स्थान की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, वे फार्म-6 भरकर बीएलओ को सौंपें या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें।बैठक में नए मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।

सीएए के तहत कानपुर की दो महिलाओं को मिली भारतीय नागरिकता

अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 169 हिंदू नागरिकों को गृह मंत्रालय ने दी नागरिकता की मंजूरी

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में कानपुर शहर की दो महिलाओं को औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।शहर के रतन स्तुति अपार्टमेंट निवासी सोनम निहलानी और शास्त्री नगर सिंधी कॉलोनी निवासी सारिका को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया है। नागरिकता मिलने के बाद दोनों महिलाओं और उनके परिजनों में

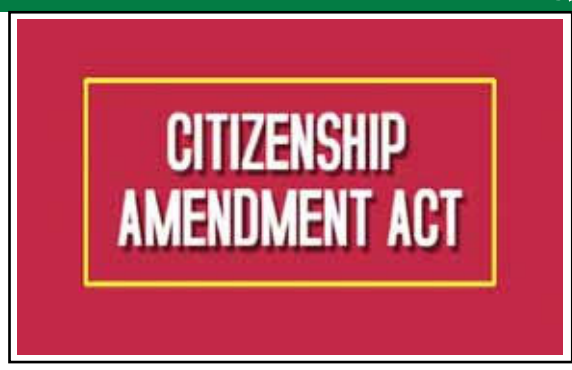

खुशी का माहौल है।

गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कार्य निदेशालय ने प्रदेश के 11 जिलों- कानपुर, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, हाथरस, मथुरा, रायबरेली, रामपुर, पीलीभीत और खीरी-के कुल 169 हिंदू नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की पुष्टि की है।

इनमें 57 महिलाएं और 112 पुरुष शामिल हैं। इन लाभार्थियों में 92 लोग बांग्लादेशी और 77 पाकिस्तानी मूल के हैं, जिन्हें सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। जनगणना कार्य निदेशालय के नागरिक प्रकोष्ठ की निदेशक शीतल वर्मा ने गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर नागरिकता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची साझा की है।

शास्त्री नगर निवासी सारिका ने बताया कि उन्होंने सीएए लागू होने के बाद अगस्त 2024 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी होने के बाद मात्र दो माह में नागरिकता मिलने की पुष्टि हो गई।

उन्होंने इसके लिए भारत सरकार और राज्य प्रशासन के प्रति आभार जताया। नागरिकता मिलने के बाद लाभार्थी अब भारतीय नागरिकों के सभी संवैधानिक अधिकारों के पात्र हो गए हैं, जिनमें मतदान का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ और रोजगार के अवसर शामिल हैं। हालांकि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया अलग से पूरी करनी होगी।

नगर निगम : पंद्रहवें वित्त आयोग से हो रहे कार्यों की जांच शुरू

» नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की सख्ती के बाद एचबीटीयू की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। पंद्रहवें वित्त आयोग की धनराशि से पचास लाख रुपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों की जांच के लिए एचबीटीयू की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने शुक्रवार को हंसपुरम, करेही, स्वर्ण जयंती विहार, दामोदर नगर सहित कई इलाकों में चल रहे कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने सड़कों को खुदवाकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परखी। इंटरलाकिंग टाइल्स हटाकर गिट्टी और डस्ट की स्थिति देखी गई। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य मानकों के अनुसार कराए जा रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।वर्तमान में नगर निगम की ओर से चालीस करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। एचबीटीयू की टीम नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर सभी कार्यों की जांच करेगी। जांच के बाद फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी।यदि जांच में किसी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा। साथ ही संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि जांच प्रक्रिया जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सांसद रमेश अवस्थी के समधी के यहां आयकर विभाग की बड़ी रेड

कांग्रेस पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी संसद रमेश अवस्थी के पुत्र से की है बिटिया की शादी

- 50 कारों से पहुंचे जांच अधिकारी , अवैध उत्खनन और वित्तीय लेनदेन की चल रही जांच
- सांसद रमेश अवस्थी के पुत्र की शाही शादी ने सभी का ध्यान खींचा था

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर/छतरपुर।आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी से जुड़ी फैक्ट्रियों पर छापेमार की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सागरङ्कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढढारी के पास स्थित खजुराहो मिनरल्स पत्थर फैक्ट्री और रामनपुरा रोड स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर एक साथ दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान करीब पचास गाड़ियों का काफिला मौके पर पहुंचा, जिनमें कुछ गाड़ियों पर शादी के स्टीकर लगे हुए थे।

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीमें मेहमान बनकर फैक्ट्रियों में दाखिल हुईं। टीम के प्रवेश के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। दोपहर से देर रात तक फैक्ट्री परिसर के भीतर दस्तावेजों की गहन जांच होती रही।

यह कार्रवाई मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितताओं और अवैध उत्खनन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है।फैक्ट्री के बाहर उन गाड़ियों की कतार लगी रही, जिनसे आयकर विभाग की टीमें छापेमारी के लिए पहुंची थीं। हालांकि देर रात तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जांच के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ और विभाग ने क्या कार्रवाई की है।बताया जा रहा है कि सात दिसंबर को छतरपुर के पूर्व विधायक

पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी

आलोक चतुर्वेदी की बेटी की शादी कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के बेटे के साथ हुई थी। यह विवाह ऋषिकेश में संपन्न हुआ था। इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचक कुमार विश्वास सहित अन्य बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। सूत्रों का कहना है कि इस शादी में हुए भारी खर्च को लेकर आयकर विभाग को शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

इसके अलावा राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि शादी में महंगे उपहारों और खर्चों ने लोगों का ध्यान खींचा। चर्चा यह भी है कि दामाद को करीब ढाई करोड़ रुपये कीमत की एक लग्जरी कार उपहार में दी गई थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में इस छापेमारी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाओं का दौर तेज है। आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

स्वराज इंडिया
कानपुर सिटी 02
सांसद रमेश अवस्थी के पुत्र के विवाह समारोह में जुटीं देश की नामचीन हस्तियां
समारोह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास सहित कई नेता राजनेता धर्मगुरु शामिल हुए

स्वराज इंडिया में शाही शादी की खबर प्रकाशित हुई थी

पिस्टल लगा कर युवक का अपहरण

40 लाख की फिरौती मांगी, दो शातिर गिरफ्तार

मैगी प्वाइंट पर चाय पीते वक्त युवक का अपहरण, सुनसान जगह ले जाकर मारपीटा

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बर्रा थाना क्षेत्र में पिस्टल दिखा कर युवक से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पिस्टल लगाकर अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

गुजैनी के वैष्णवी विहार निवासी सुनीता सचान ने बर्रा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा प्रियांशु बीते सात दिसंबर की रात बर्रा स्थित मैगी प्वाइंट पर चाय पी रहा था। इसी दौरान घाटमपुर के

जवाहर नगर निवासी मोनू सचान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रियांशु की कनपटी पर पिस्टल लगा दी। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाया गया।पीड़िता के अनुसार मोनू के साथ हर्षित सचान, शिवम सचान, कृष्णा सैनी और आयुष तिवारी भी मौजूद थे, जो दूसरी बाइक से पहुंचे थे। आरोप है कि सभी ने मिलकर प्रियांशु के साथ मारपीट

की और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद 40 लाख रुपये घर से मंगाने का दबाव बनाया गया।

जब प्रियांशु ने इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थता जताई, तो आरोपितों ने पिस्टल उसके हाथ में देकर कहा कि या तो एक घंटे में 20 लाख रुपये का इंतजाम कर लो या फिर आत्महत्या कर लो।किसी तरह जान बचाकर प्रियांशु वहां से भाग निकला और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात घाटमपुर स्थित मोनू सचान के घर दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी छत से कूदकर भागने लगे, इस दौरान मोनू के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि कृष्णा सैनी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बर्रा इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है और मामले की जांच जारी है।

हड़ताल के पहले दिन उफान पर अधिवक्ता

तहसील से कोतवाली तक सड़कों पर दिखा आक्रोश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थानांतरण के विरोध में घोषित कलमबंद हड़ताल के पहले दिन शुक्रवार को अधिवक्ताओं का आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आया। सुबह से ही बार एवं लायर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता उप निबंधक कार्यालय के पास एकत्र होने लगे और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन की शुरुआत की। नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं का जुलूस उप निबंधक कार्यालय से सीओ कार्यालय पहुंचा, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

इसके बाद जुलूस नई तहसील भवन पहुंचा और एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। यहीं नहीं, अधिवक्ताओं का जुलूस ककवन रोड से होते हुए जीटी रोड की ओर बढ़ा और अंत में कोतवाली गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कोतवाली गेट पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील से दूर रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाने का फैसला न सिर्फ अधिवक्ताओं बल्कि आम जनता के हितों के भी खिलाफ है।

हड़ताल से तहसील और रजिस्ट्री के काम ठप

हड़ताल के चलते रजिस्ट्री सहित तहसील के कई महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह ठप रहे। दूर-दराज से आए फरियादियों को बिना काम कराए लौटना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन और स्थानीय कार्यालयों को भी कार्य में बाधा आई, जिससे दिन भर राजस्व और प्रशासनिक काम प्रभावित रहे।

अधिवक्ताओं की चेतावनी, प्रशासन सतर्क

अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि नया निर्णय शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस, खुफिया विभाग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे और हालात पर कड़ी नजर रखी गई।

एसडीएम ने धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

एमएसपी पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश, अभिलेखों की हुई जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। खरीफ विपणन वर्ष 2025 के तहत मूल्य समर्थन योजना (एमएसपी) के अंतर्गत शुक्रवार को उपजिलाधिकारी बिल्हौर ने शिवराजपुर स्थित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों पर किसानों से की जा रही खरीद, तौल व्यवस्था और अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गई।

निरीक्षण के समय शिवराजपुर प्रथम व द्वितीय के विपणन निरीक्षक अमित सिंह, शिवराजपुर तृतीय की विपणन निरीक्षक स्वाति तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी राज कमल उपस्थित रहे। अभिलेखों के अनुसार 12 दिसंबर 2025 तक शिवराजपुर प्रथम केंद्र पर 1702.40 क्विंटल, द्वितीय केंद्र पर 1659.60 क्विंटल तथा तृतीय केंद्र पर 1715.40 क्विंटल धान की खरीद दर्ज की गई है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के केंद्र पर 935.60 क्विंटल धान का क्रय किया जा चुका है।

मोटे अनाज की खरीद के संबंध में बताया गया कि शिवराजपुर प्रथम केंद्र पर 2036.50 क्विंटल और द्वितीय केंद्र पर 2478.50 क्विंटल बाजरे की खरीद हुई है। उपजिलाधिकारी डॉक्टर संजीव दीक्षित ने अधिकारियों को शासन की मंशानुसार धान की खरीद का शत-प्रतिशत लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही खरीदे गए खाद्यान्न की सुरक्षित ढुलाई और भंडारण सुनिश्चित करने, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, पर विशेष जोर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने मंगलवार को आराजी ईशेपुर बूथ पर बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बूथ स्तरीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मतदाता सूची में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों की बारीकी से जांच की।

बैठक में विनय यादव ने बताया कि आराजी ईशेपुर बूथ की मतदाता सूची में डबल, डुप्लीकेट, मृतक एवं शिफ्टेड श्रेणी के कुल 94 नाम चिह्नित किए गए हैं। इनमें डुप्लीकेट 4, डबल 6, मृतक 17 और शिफ्टेड 67 मतदाता शामिल हैं, जिन्हें सूची से विलोपित किए जाने की प्रक्रिया में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सभी परिवार अपने-अपने मतदाता नामों का सत्यापन अवश्य करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए। बैठक में स्थानीय लोगों ने अभियान में सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विभिन्न गांवों के बूथ लेवल एजेंट्स भी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम ने कानपुर विश्वविद्यालय में एक सैकड़ा शिक्षकों को किया सम्मानित

शिक्षक सम्मान-25

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। छात्रों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर चयनित कानपुर जिले के एक सैकड़ा शिक्षकों को आज छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रतिष्ठित समाचार पत्र की ओर से शिक्षक सम्मान पहल के तहत प्रदान किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने की। इस मौके पर अंगद सिंह सहित शहर के एक सैकड़ा विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षाविद भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि कानपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने ऑनलाइन मतदान के माध्यम से अपने पसंदीदा शिक्षकों का चयन किया। इन्हीं वोटों के आधार पर एक सैकड़ा शिक्षकों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए शिक्षकों में राम सहाय इंटर कॉलेज बैरी शिवराजपुर के अरविंद यादव, विन्यास पब्लिक स्कूल चौबेपुर से अरुण कुमार, वीरांगना बाई अवंती विद्यालय शिवराजपुर से अजयवीर सिंह

सहित कानपुर के अनेक स्कूलों के शिक्षक शामिल रहे। जिन्हें मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाचार पत्र के संपादक नीरज तिवारी, विनय तिवारी और मनोज कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह के दौरान छात्रों द्वारा शिक्षकों को दिए गए सम्मान और स्नेह को देखकर कार्यक्रम में उत्साह और गरिमा का विशेष वातावरण देखने को मिला।

सम्पादकीय

निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर सुप्रीम राय

देश में लंबे समय से यह मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में रहा है कि विषम परिस्थितियों में एक त्रासदी से मुक्ति हेतु इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं। समय-समय पर अदालती फैसलों ने मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। साथ ही कोशिश की गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न किया जा सके। हाल ही में एक ज्वलंत प्रसंग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय युवक का है, जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत की टिप्पणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चय ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालती फैसला नैतिक प्रेरणा का स्रोत भी बना। कालांतर में जिसके चलते वर्ष 2018 में एक संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। साथ ही इसके लिये एक आवश्यक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। जिसका मकसद था कि समाज में कहीं इस छूट का दुरुपयोग आपराधिक स्वार्थों के लिये न किया जा सके।वर्ष 2023 में, अदालत ने इन दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का प्रयास किया।

जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों द्वारा स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देश में वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। बहरहाल, वर्तमान मामले में बार-बार की गई अपीलें, इससे जुड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ित को घर में दी जाने वाली देखभाल अपर्याप्त ही साबित होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य का समर्थन भी पर्याप्त नहीं रहा है।

इसके अलावा ऐसे मामलों से जुड़ी अनसुलझी नैतिक दुविधाएं असमंजस की स्थिति पैदा करती रही हैं। जो उनके परिवारों के लिये भी एक त्रासदी की स्थिति है। जहां परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जूझ रहे होते हैं, वहीं रोगी के उपचार से जनित आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, अदालत को जटिल परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार की पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

डीपसीक गाथा में भारत के लिए मौजूद सबक

ज्योति मल्होत्रा

डीपसीक की धूमधाम के तुरंत बाद, भारत ने बुनियादी मॉडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं का एक समुच्चय घोषित किया। हालांकि डीपसीक व्यावसायिक उद्यम है, जिसका मकसद वैश्विक बाजारों में मुनाफा कमाना है। वहीं, भारतजेन रणनीतिक राष्ट्रीय मिशन है, जो...
डीपसीक की धूमधाम के तुरंत बाद, भारत ने बुनियादी मॉडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं का एक समुच्चय घोषित किया। हालांकि डीपसीक व्यावसायिक उद्यम है, जिसका मकसद वैश्विक बाजारों में मुनाफा कमाना है। वहीं, भारतजेन रणनीतिक राष्ट्रीय मिशन है, जो तकनीकी संप्रभुता प्राप्ति पर केंद्रित है। इसके जरिये सार्वजनिक भलाई में संतुलन बनाकर चलना होगा।

इस वर्ष जनवरी में, एक अल्पज्ञात चीनी स्टार्टअप ने नाटकीय घोषणा की, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की दुनिया को हिला दिया। कंपनी थी 'डीपसीक', जिसने अपने लार्ज लेंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम को अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों, जैसे कि चैट जीपीटी के विकसित मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी किया।जिस चीज़ ने सब को हैरान किया, वह था इसको विकसित करने में आई बेहद कम लागत, यह सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करके सिलिकॉन वैली के दिग्गजों द्वारा विकसित किए एआई की तुलना में अंश मात्र है। इस नई घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि एआई क्षेत्र में चीन बहुत आगे है और अमेरिका तकनीकी विकास में एकमात्र प्रभावी शक्ति नहीं रहा। अब, विज्ञान पत्रिका 'नेचर' ने डीपसीक के संस्थापक लियांग वेनफेंग को 2025 के दौरान वैश्विक स्तर के प्रमुख वैज्ञानिक विकास के पीछे के शीर्ष 10 लोगों में नामित किया है। डीपसीक का सामान्य उद्देश्य 'वी-3 मॉडल' और उन्नत मॉडल, 'आर-1' ने केवल सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी बल्कि करीब एक वर्ष में एआई परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव भी लाए हैं। 'आर-1' एक तर्कशील एलएलएम है जो गणित और कोडिंग में जटिल कार्यों को संभाल सकता है। चीनी फर्म ने अमेरिकी कंपनियों से एक

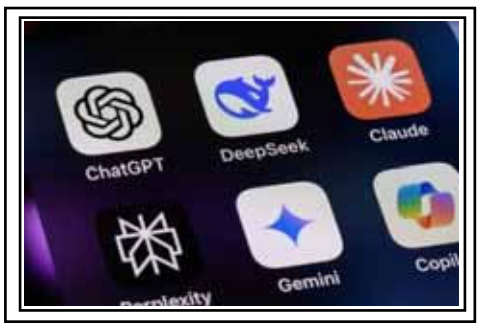

कदम आगे बढ़ते हुए डीपसीक को एक ओपन मॉडल बना दिया, जिसके तहत शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉडल के एल्गोरिद्म अपने अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति है। कंपनी ने यह राज़ भी खोला कि वह 'प्रशिक्षण' लागत इतनी कम कैसे रख पाई।सभी एलएलएम को पहले विशाल मात्रा में डेटा भरना पड़ता है या उन्हें कुशल बनाने के लिए 'डेटा-प्रशिक्षित' करना पड़ता है। एक उद्योग सर्वेक्षण से पता चला है कि इस वर्ष चीनी मॉडल एआई बाजार में तेजी से आगे बढ़े हैं, जिसकी बदौलत वे इस तकनीक के वैश्विक उपयोग का एक-तिहाई हिस्सा बन चुके हैं। टोकन वॉल्यूम में इंग्लिश के बाद चीनी भाषा के प्रॉम्प्ट दूसरे स्थान पर हैं। यह दर्शाता है, चीनी मॉडल वैश्विक स्तर पर अच्छा कर रहे हैं और चीन के भीतर भी व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे। टोकन डेटा की वे इकाइयां हैं जिन्हें एआई मॉडल द्वारा ट्रेनिंग और अनुमान के दौरान संसाधित किया जाता है व ये भविष्यवाणी, सृजन और तर्क को सक्षम करने में मदद करते हैं। डीपसीक की धूमधाम के तुरंत बाद, भारत ने भी बुनियादी मॉडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं का एक समुच्चय घोषित किया, जिसमें एलएलएम, लघुभाषा मॉडल और भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। इस योजना में 'डिजिटल इंडिया भाषिणी' (भारतीय भाषाओं के लिए एआई भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म), भारतजेन (सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मल्टीमॉडल एलएलएम), सर्वम-1 एआई मॉडल (10 भारतीय भाषाओं के लिए एलएलएम), चित्रलेखा (वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म) और 'हनुमान'स एवरेस्ट' 1.0 (35 भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषाई एआई प्रणाली) का विकास करना शामिल है।

आम उपभोक्ता को मिले घटी ब्याज दरों का लाभ

रेपो रेट में कटौती

ज्वाला सिंह दास

यदि आम आदमी को सस्ते कर्ज का लाभ मिलेगा, तो ईएमआई में कमी आएगी और ऋण लेने वालों को फायदा होगा। इससे घरों और वाहनों की मांग बढ़ेगी और रियल स्टेट उद्योग को ब्याज दरों में कटौती से राहत मिलेगी।हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा हाल में ब्याज दरों में कटौती के मद्देनजर रेपो रेट में 25 आधार अंकों की जो कटौती की गई है, उसका लाभ बैंकों द्वारा विभिन्न वर्ग के ग्राहकों तक पहुंचाया जाना जरूरी है।

हाल ही में आरबीआई द्वारा आयोजित मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण देश में महंगाई का कम होना और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3 प्रतिशत होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी को दूर करने और इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर घटाने का प्रमुख कारण महंगाई पर नियंत्रण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2025 में खुदरा महंगाई पिछले 10 साल के न्यूनतम 0.25 प्रतिशत पर और थोक महंगाई 27 महीने के निचले स्तर 1.21 प्रतिशत से नीचे आ गई। महंगाई में यह कमी मुख्यतः सब्जियां, फल, अंडे, फुटवियर, अनाज और उससे बने उत्पाद, बिजली, परिवहन और संचार जैसी वस्तुओं के दामों में गिरावट के कारण हुई है। इसके अलावा, हालिया

जीएसटी सुधारों ने भी महंगाई नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर, 2025 में शाकाहारी थाली की कीमत 27.8 रुपये और मांसाहारी थाली की कीमत 54.4 रुपये रही। विभिन्न शोध रिपोर्टों में, बेहतर खाद्यान्न उत्पादन और अच्छे मानसून के कारण कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को मिल रही अनुकूलताओं के चलते आगामी महीनों में महंगाई और कम हो सकती है।

भारत के विकास पर कई रिपोर्टों में कहा गया है कि टैक्स व महंगाई घटने से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और भारत की क्रेडिट रेटिंग सुधर रही है, लेकिन तेज विकास के मद्देनजर कर्ज सस्ता किए जाने की जरूरत लगातार बनी हुई है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार सरकार के बड़े फैसलों से उपभोग आधारित बढ़ोतरी को बढ़ावा मिलेगा। 'जीएसटी की कम दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी और इस वर्ष शुरू की गई आयकर कटौती एवं ब्याज दरों में कटौती का पूरक बनेंगी।

इन बदलावों से चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में उपभोग वृद्धि का एक बड़ा चालक बन सकता है।'उल्लेखनीय है कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की मध्यवर्ती आर्थिक समीक्षा में कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाए जाने और महंगाई में कमी का लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिला है। लेकिन अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक मुश्किलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उद्योगों और व्यापार को आर्थिक और वित्तीय सहारा जरूरी है।

विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विकास की डगर पर आगे बढ़ रहा है।

लेकिन अब भारत को 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आर्थिक-वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को और तेजी देने तथा उद्योग-कारोबार के लिए आसान ब्याज दरों पर कर्ज जुटाकर निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।

अब ब्याज दर घटाए जाने के कारण सस्ते कर्ज से आर्थिक गतिविधियों में तेजी की संभावना विकास दर को बढ़ाने के लिए सकारात्मक संदेश है।

जैना पैलेसः पांच सौ करोड़ की कीमती जमीन में फैला 'रायता'

» जैना पैलेस की जमीन हथियाने को लेकर उठा बड़ा सवाल

» कोर्ट के फैसले और केडीए की भूमिका पर पीड़ित उठा रहे सवाल

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया कानपुर सिटी 02

जैना पैलेस पर कब्जे का विवाद गहराया, आवंटी पहुंचे केडीए

भू-माफिया पर मिलीभगत कर कब्जा करने के आरोप, सुरक्षा की मांग

रतनलाल नगर में जैना पैलेस की जमीन पर माफियाओं की जुगलबंदी

स्वराज इंडिया कानपुर सिटी 06

रतनलाल नगर में जैना पैलेस की जमीन पर माफियाओं की जुगलबंदी

» वर्ष 1989 में टेक चन्द जैना को व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु लीज पर दी गई थी भूमि पर भू-माफिया सक्रिय

» कब्जे को लेकर विवाद गहराया, वरिष्ठ पार्षद नवीन पंडित ने केडीए वीसी से की शिकायत

कानपुर। महानगर के रतनलाल नगर स्थित जैना पैलेस से जुड़े मामले ने अब शहर ही नहीं, बल्कि करोड़ों की कीमती जमीन में फैले बड़े खेल की ओर ध्यान खींच लिया है। लगभग पांच सौ करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को लेकर वर्षों से चले आ रहे अव्यवस्था और कथित भू माफिया गठजोड़ पर अब कार्रवाई की उम्मीद जगी है।

पूर्व सांसद राजाराम पाल की अगुवाई में जैना पैलेस के निवासियों और व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब तीस वर्ष पूर्व जैना पैलेस के तत्कालीन मालिक द्वारा धन लेकर फ्लैट और दुकानें आवंटित की गई थीं, जिनमें लोग वर्षों से निवास और व्यापार कर रहे हैं।

इसके बावजूद अब अचानक की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों को बेघर होने की कगार पर ला खड़ा किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि करोड़ों की इस कीमती जमीन को लेकर लंबे समय से अवैध खेल चल रहा है और उसी के दबाव में आम लोगों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। एक टावर को पूरी तरह ध्वस्त किए जाने और अन्य भवनों को गिराने की तैयारी ने लोगों की चिंता और आक्रोश को और बढ़ा दिया है।

धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पांच सौ करोड़ रुपये मूल्य की जमीन में फैले अव्यवस्था, फर्जीवाड़े और भू माफिया नेटवर्क को उजागर किया जाए।

लोगों का कहना है कि यदि सही जांच हुई तो सच्चाई सामने आएगी और निर्दोष परिवारों को राहत मिलेगी।इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और अधिवक्ता शामिल रहे। सभी की एक ही मांग रही कि वर्षों से बसे लोगों के आशियाने बचाए जाएं और करोड़ों की जमीन में फैले खेल पर सख्त कार्रवाई हो।अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।

यदि जांच निष्पक्ष और ठोस हुई, तो यह मामला न केवल जैना पैलेस के निवासियों के लिए राहत बनेगा, बल्कि कानपुर में करोड़ों की जमीन से जुड़े अवैध खेल पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी और सकारात्मक पहल साबित हो सकता है।

हमने कोर्ट के आदेश पर केडीए से नई लीज करवाई है। इसमें अब कोई विवाद नहीं है,भाजपा से जुड़े अनुपम मिश्र 50 लाख रुपए दलाली के मांग रहे थे, हमने मना कर दिया तो इस तरह से बदनाम किया जा रहा है।

मनोज कुमार सिंह
कथित मालिक जैना पैलेस

केआईटी कॉलेज में परीक्षा विवाद पर उबाल, कांग्रेस ने संभाला मोर्चा

जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला कॉलेज पहुंचे, प्रबंधन से वार्ता कर छात्रों को दिया समर्थन

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। महाराजपुर के रुमा स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) में परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने पहले परीक्षाएं कॉलेज परिसर में ही कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में अचानक परीक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। इस फैसले से नाराज छात्र बीते तीन दिनों से धरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ग्रामीण कानपुर के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला अन्य पार्टी नेताओं के साथ कॉलेज पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने बताया कि प्रवेश के समय उन्हें संस्थान को ऑटोनोमस बताकर अधिक फीस वसूली गई, जबकि अब न तो वही व्यवस्था लागू की जा रही है और न ही पूर्व निर्धारित विषयों और सिलेबस के अनुसार परीक्षाएं कराई जा रही हैं। छात्रों ने अलग सिलेबस थोपे जाने और उत्पीड़न के भी आरोप लगाए।कांग्रेस नेताओं ने कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. बृजेश वार्ष्णेय से मुलाकात कर छात्रों की सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान करने की मांग की। इस दौरान संदीप शुक्ला ने छात्रों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके हितों की लड़ाई में हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी और यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

स्वराज इंडिया
कानपुर सिटी
केआईटी कॉलेज में परीक्षा केंद्र बदलने पर तीसरे दिन भी विरोध जारी

घाटमपुर-मूसानगर रोड बना कूड़ा डंपिंग ग्राउंड, बदबू से राहगीर बेहाल

» वर्षों से सडक़ किनारे फेंका जा रहा कूड़ा और शराब ठेकों का कचरा

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। घाटमपुर से मूसानगर जाने वाली सडक़ के किनारे नगर पालिका की ओर से वर्षों से क्षेत्र का कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर आसपास संचालित शराब ठेकों से निकलने वाला सारा कचरा भी लगातार डाला जा रहा है, जिससे सडक़ किनारे गंदगी का अंबार लग गया है।कूड़े के ढेर से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बदबू और गंदगी के चलते सांस संबंधी बीमारियों, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद घाटमपुर नगर पालिका की ओर से इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।स्थानीय नागरिकों का दावा है कि यहां डाला जा रहा कूड़ा सीधे नगर पालिका के वाहनों द्वारा फेंका जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर आंख मूंदे हुए हैं। लोगों ने मांग की है कि कूड़ा डंपिंग को तत्काल बंद कराया जाए और क्षेत्र की नियमित सफाई कराकर स्वास्थ्य जोखिम से राहत दिलाई जाए।

लेखपाल के संरक्षण में सरकारी नाले पर कब्जा कर बना लिए प्लाट

ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत राय गोपालपुर में प्लाटिंग के नाम पर बड़े भूमि घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंकज दुबे नामक एक प्लाटिंगकर्ता द्वारा जिस भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है, उसके किनारे से गुजर रहे सरकारी नाले को अवैध रूप से पाट दिया गया है, जिससे जल निकासी बाधित होने का खतरा बढ़ गया है।

ग्रामीणों के अनुसार, इस मामले की शिकायत जब क्षेत्र के मौजूदा लेखपाल अनिल वर्मा से की गई, तो उन्होंने मौके पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होने से साफ इनकार कर दिया और शिकायत को झूठा बताया। लेखपाल का कहना है कि नाले पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। हालांकि, स्थानीय सूत्रों का दावा है कि प्लाटिंगकर्ता को संरक्षण देने के लिए लेखपाल की भूमिका संदिग्ध है और कथित रूप से नाले पर कब्जा कराने में मिलीभगत की बात कही जा रही है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि इसके बदले मोटी रिश्वत ली गई है, हालांकि इन आरोपों की स्वराज इंडिया द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सरकारी नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव और अन्य समस्याओं से बचा जा सके।

कानपुर सेंट्रल का डीआरएम ने किया निरीक्षण, कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश

सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट मॉडल पर विकसित करने का कार्य चल रहा

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) रजनीश अग्रवाल ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन और आसपास के रेलवे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का बारीकी से जायजा लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

डीआरएम ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक पहुंचकर ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग व्यवस्था और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पनकी धाम, अनवरगंज, गोविंदपुरी और कानपुर सेंट्रल पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया।

उन्होंने आई.डब्ल्यू. विभाग और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने व समयसीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

ज्ञात हो कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिसका कार्य तेज़ी से चल रहा है और वर्ष 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है।निरीक्षण के दौरान डीआरएम पनकी पावर प्लांट और लोको शेड भी पहुंचे, जहां उन्होंने तकनीकी व्यवस्थाओं और संचालन की गुणवत्ता की जानकारी ली।

इस दौरान स्टेशन डायरेक्टर, एडीआरएम, कमर्शियल विभाग के अधिकारी, इंजीनियरिंग टीमें और आरपीएफ जवान मौजूद रहे।रेलवे प्रशासन ने बताया कि आगामी माघ मेले को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधाओं को महाकुंभ स्तर की व्यवस्था के अनुरूप मजबूत किया जा रहा है,

जिससे भीड़ प्रबंधन और सुविधा दोनों में बेहतर परिणाम मिल सकें।

नलकूप सरकारी प्राइवेट मोटर लगाकर करने लगे सिंचाई

» शिकायत डीएम तक पहुंची, नलकूप विभाग के अवर अभियंता बोले जांच की जाएगी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड मलासा के कैलई गांव स्थित सरकारी नलकूप में निजी मोटर डाल कर सिंचाई करने की शिकायत की गई है। कैलई निवासी विकास ने बताया कि गांव में सिंचाई के लिए 80 बीपीजी नलकूप लगा हुआ है। यह दो साल पहले से ही खराब हो गया था। विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसमें गांव के एक ही व्यक्ति ने मोटर डालकर संचालित कर लिया है।

आरोप है कि वह अपनी ही जमीन की सिंचाई करते हैं। जिससे अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नलकूप की जांच कर अन्य किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराए जाने की फरियाद जिलाधिकारी कपिल सिंह से की है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नलकूप विभाग के अवर अभियंता संतोष पाल ने बताया है कि शिकायत की जानकारी मिली है मंगलवार या बुधवार को जांच की जायेगी।

रूरा में अवैध खनन: विभागीय चुप्पी से माफिया बेखौफ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। तहसील अकबरपुर के रूरा थाना क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी खनन का खेल लगातार फल-फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि बार-बार शिकायतों और खबरों के बावजूद न तो पुलिस की सक्रियता दिखाई दे रही है और न ही संबंधित विभागों की ओर से कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालात यह हैं कि भारी मशीनों और डंपरों और ट्रैक्टरों के जरिए खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है

» स्थानीय पुलिस के बाद अब सिंचाई विभाग की भूमिका पर भी उठे सवाल

» बालू खनन में रूरा नगर पंचायत के सभासद का नाम आया सामने, हो सकती है एफआईआर!

तिगांई गांव के पास पटरी पर बालू खनन में नगर पंचायत रूरा के सभासद संजय यादव का नाम सामने आया है, बताया गया है कि स्थानीय भाजपा नेता के सरंक्षण से मिट्टी और बालू खनन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस पूरे अवैध खनन नेटवर्क में केवल खनन माफिया ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। खास तौर पर सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। नहरों, रजवाहों और सरकारी भूमि की मिट्टी निकालने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के कारण खेतों की रजबहों की मेड़ें कमजोर हो रही हैं और भूमि का कटाव लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही पर्यावरणीय असंतुलन भी गहराता जा रहा है। कई स्थानों पर पेड़ों की कटान और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की गश्त केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

अवैध खनन से जुड़े वाहन बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अवैध खनन को लेकर उठ रहे सवालों के बाद प्रशासन और उच्च अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर रूरा क्षेत्र यूं ही अवैध खनन का सुरक्षित ठिकाना बना रहेगा।

जिम्मेदारों के बयान...

रूरा के पास नहर पटरी के खनन की जानकारी एसडीएम को दी है, मामले में कार्यवाही होगी।
कपिल सिंह, डीएम कानपुर देहात

जेई को भेज कर जांच करवा रहे हैं, इसके बाद बालू खनन करने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
महेन्द्र कुमार सिंह, एक्सियन सिंचाई विभाग

आधी रात को किराना व्यापारी के यहां लाखों की चोरी

» सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोरियां शुरू, कई मामलों का अब तक नहीं हो सका खुलासा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पुखरायां मेंन रोड निवासी किराना व्यापारी के यहां चोरों ने हजारों रुपए की नगदी व माल चोरी कर लिया । पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुखरायां मेन रोड निवासी मुकेश मित्तल ने बताया कि उसकी मेंन रोड पर किराने की होलसेल की दुकान है। जहां पर रात लगभग 10-30 बजे दुकान बंद करके दूसरी मंजिल मकान में चले गये ।

आधी रात में चोर पेड़ के रास्ते छत में चढ़ गए मकान का शीशा तोडक़र अंदर घुस गए और सीडी से उतरकर दुकान में रखी हजारों रुपए की नगदी व सामान चोरी कर लिया सीसीटीवी लगे कैमरे में दोनों कैद हो गये।

व्यापारी मुकेश मित्तल ने बताया कि रात लगभग 11-00 बजे तक में रोड में आवाज रहती है फिर भी चोरों ने मौका पाकर चढ़ गए और दरवाजा कई घंटे तक तोड़ते रहे जब दरवाजा नहीं टूटा हुआ नहीं खुला तो मकान का शीशा तोडक़र सीढ़ी से उतरकर नीचे दुकान में पहुंच गए।

गोलक में रखी नगदी व कीमती सामान भरकर भाग गए। सुबह दुकान मालिक को चोरी का पता चला और उन्होंने पुखरायां चौकी इंचार्ज को सूचना दी। भोगनीपुर इंस्पेक्टर अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि जांच शुरू कर दी गई है तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर चोरों का पता लगाया जाएगा।

बता दें कि इससे पूर्व भी कई चोरियां हो चुकी हैं

जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

एएनएम ने ज़हर खाकर दी जान देने की कोशिश सुसाइड नोट में फार्मासिस्ट पर संगीन आरोप

विभागीय प्रताड़ना ने तोड़ दी हिम्मत!

» सुसाइड नोट में लिखा कि एक ही दिन में पांच-पांच जगह ड्यूटी कराई जा रही थी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या। अयोध्या जनपद के रूदौली क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुजागंज में तैनात एएनएम अनीता ने कथित विभागीय प्रताडना से तंग आकर ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। ज़हर खाने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों, विशेषकर एक फार्मासिस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद एएनएम को गंभीर हालत में रूदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

एएनएम द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में लिखा है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाकर एक साथ कई स्थानों पर टीकाकरण ड्यूटी लगाई जा रही थी। उनसे एक ही दिन में पांच-पांच जगह ड्यूटी कराई जा रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थीं।

सुसाइड नोट में रूदौली सीएचसी में तैनात आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट धनीराम पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि फार्मासिस्ट द्वारा उन्हें लगातार ड्यूटी का दबाव दिया जाता था और किसी कारणवश ड्यूटी न कर पाने पर पैसों की मांग की जाती थी। पीड़िता का दावा है कि कई बार मजबूरी में उन्होंने पैसे भी दिए।

जानकारी के अनुसार, ज़हर खाने से पहले एएनएम अनीता ने रूदौली सीएचसी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी संदेश भेजा था। संदेश में लिखा कि वह ज़हर खाने जा रही हैं और उन्हें लगातार

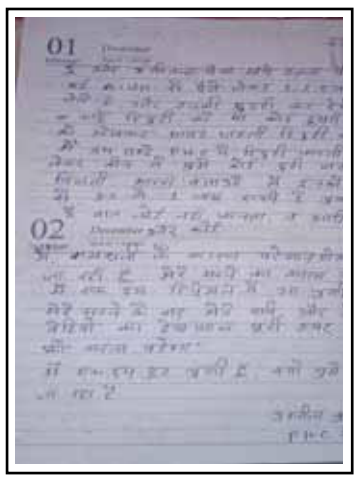

प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिससे वह और अधिक तनाव में थीं। शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे अनीता ने सुसाइड नोट लिखने के बाद ज़हर खा लिया। ज़हर खाने की जानकारी उनके पति प्रवेश कुमार को एसएससी ग्रुप के माध्यम से मिली। परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक अनीता ज़हर खा चुकी थीं। आनन-फानन में उन्हें एंबुलेंस से रूदौली सीएचसी ले जाया गया।

इस घटना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुजागंज की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 10 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र में केवल एक ही एएनएम तैनात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमरजेंसी डिलीवरी की स्थिति में महिलाओं को मजबूरन निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार, जब भी एएनएम को फोन किया जाता है, तो जवाब मिलता है कि वह टीकाकरण ड्यूटी पर बाहर गई हुई हैं। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। गौरतलब है कि करीब एक साल पहले इसी शुजागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट ने रात के समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और कर्मचारियों पर बढ़ते मानसिक दबाव की ओर इशारा कर रही हैं।

शादी के दिन ब्यूटी पार्लर से प्रेमी संग निकल गई दुल्हन पुलिस कर रही तलाश

शहर के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह था, बिना दुल्हन के ही बारात वापस हो गई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की गुरुवार को शादी होनी थी। गेस्ट हाउस से लेकर घर तक खुशियों का माहौल था।

इसी बीच शहर स्थित एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गए युवती ने तैयार होने के बाद अपने प्रेमी को बुलाया और उसके साथ चली गई। अचानक से युवती के गायब होने से परिजनों समेत वर पक्ष में हडक़ंप मच गया। जहां बाद में बिना दुल्हन के ही बारात बैरंग वापस हो गई। युवती के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शहर के एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार को शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। बाराती भी आ चुके थे। गेस्ट हाउस में एक ओर बारात की तैयारी चल रही थी। तो दूसरी ओर दुल्हन तैयार होने के लिए परिजनां के साथ शहर स्थित एक ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। सूत्रों के अनुसार जहां ब्यूटी पार्लर में युवती को दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा था। जहां तैयार होने के बाद ब्यूटी पार्लर से निकल कर युवती प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर चली हो गई। इधर अचानक से युवती को प्रेमी के साथ जाते देख साथ में मौजूद परिजनों ने उसके माता-पिता को फोन से जानकारी दी। युवती के गायब होने की जानकारी होते ही शादी वाले घर में हडक़ंप मच गया। काफी प्रयास के बाद युवती का कहीं पता नहीं चल सका।

युवती के पिता ने कोतवाली पुलिस को युवती के लापता होने की तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को एक शादी होनी थी। दुल्हन ब्यूटी पार्लर सजने के लिए गई थी। जहां से वह गायब हो गई। परिजनों की तहरीर पर युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जल्लाद से कम नहीं थे गोवंश को पकड़ने वाले

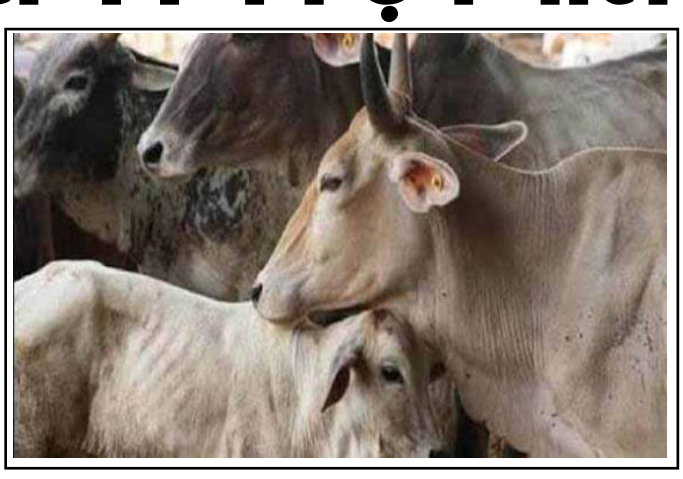

जंगल के भीतर गोवंशों को जिस बेरहमी से बांधा गया था, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। छोटी-छोटी रस्सियों से कसकर बांधे गए 37 गोवंश न चल पाने की हालत में पड़े मिले। आसपास लगे तंबू, बिस्तर और खाना पकाने के बर्तन इस बात की गवाही दे रहे थे कि तस्कर लंबे समय तक यहां ठहरने की तैयारी में थे। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए, लेकिन उनके पीछे छूटे हालात ने साफ कर दिया कि गोवंशों को पकड़ने वाले किसी जल्लाद से कम नहीं थे। गौवंश की इस बरामदगी ने पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संदिग्ध हालात में युवक ने की आत्महत्या

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान कस्बे में शनिवार सुबह एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।मृतक की पहचान रसधान कस्बा निवासी 32 वर्षीय कृष्ण कुमार के रूप में हुई है।थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी था।

पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नये अध्यक्ष!

केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 में अखिलेश यादव को रोकने के साथ योगी को भी घेरने की कोशिश की!

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिये पंकज चौधरी का नाम आगे कर केंद्र ने 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए को कड़ी टक्कर देने के साथ योगी की घेराबंदी का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिये जब से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम चर्चा में आया तब से यूपी में खास कर पूर्वांचल में की राजनीति में माहौल गर्म हो गया है। जले, कटे, सिर दर्द, बदन दर्द के तेल निर्माता से राजनीतिज्ञ बने पुराने धनाढ्य पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्वांचल में अपने जाति के बड़े नेता हैं। 1991 से एक चुनाव 2004 का छोड़ कर वह लगातार महराजगंज से सांसद चुने जा रहे हैं।

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का संकेत देकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती पेश कर दिया बल्कि ज्वलंत हिंदुत्व के ब्रांड अम्बेसडर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ में ही घेरने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिये अब तक जितने भी प्रयोग किये गये ये उनमें सबसे मास्टर स्ट्रोक है। फिलहाल यह भाजपा है अंतिम निर्णय आने के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। योगी के घेरेबंदी की पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी।लेकिन हर बार केन्द्री पटाखा फुस्स हो जाता था। जानकर इसे योगी आदित्यनाथ के निर्विघ्न उड़ान में बाधा मान रहे हैं।11 मई 2025 को गोरखपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन था। दूसरे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया। बताते हैं कि मुख्यमंत्री उस दिन गोरखपुर में थे, लेकिन वह इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। इन तीनों नेताओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घनिष्ठता कम है। लेकिन तीनों एक साथ हैं। भाजपा के जानकार कहते हैं कि नेताओं की मंशा के अनुसार जो खबर आ रही है यदि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो यूपी में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को सजग हो जाना चाहिये। अब उन्हें पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा।भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अखिलेश यादव के पीडीए से लड़ने के लिये यह अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन यदि यह निर्णय बैक फायर किया तो घर में स्थित तनावपूर्ण हो जायेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि यूपी में भाजपा का सपा से पिछड़ने का नेतृत्व ऐसा रास्ता निकलेगा जो राह कम रार को ज्यादा हवा दे सकती है।यह निर्णय योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर जिले, मंडल और पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को कमजोर करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वह आपसी मधुरता नहीं है, वर्तमान में जिसकी दरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वस्त महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के घर 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के पहुंच गये थे। तब बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के 200 मीटर पैदल चल कर पैदल ही पंकज चौधरी के घर पहुंच गये थे।

मेरठ जेल में बंद कातिल मुस्कान अपनी बच्ची पर लुटा रही प्यार

»क्वारैंटाइन बैरक में रहकर कर रही अपनी लड़की की देखभाल

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ। नीले ड्रम में पति सौरभ की हत्या कर शव को सीमेंट से जमा देने के मामले में जेल में बंद मुस्कान पिछले दस महीनों से जिला कारागार में निरुद्ध है। 24 नवंबर को उसने जेल अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा गया है।

बताया गया है कि प्रसव से पहले मुस्कान कॉमन बैरक में रह रही थी, जहां करीब 30 महिला बंदी थीं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे क्वारैंटाइन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां वह नवजात बेटी के साथ रह रही है।जेल प्रशासन की ओर से उसे फोल्डिंग बेड, पतला गद्दा और ओढ़ने के लिए कंबल उपलब्ध कराया गया है।

इससे पहले वह जेल में सिलाई-बुनाई का काम करती थी, लेकिन अब पूरा समय बेटी की देखभाल में बिता रही है।मां बनने के बाद मुस्कान का पूरा ध्यान बच्ची पर केंद्रित है।

सीमित संसाधनों के बीच वह झुनझुना और एक छोटे हाथी के टूटे हुए खिलौने से अपनी बेटी को बहलाती नजर आती है। जेल के भीतर मां और नवजात की देखरेख जेल प्रशासन द्वारा तय नियमों के अनुसार की जा रही है।

रामगंगा नदी में मृत मिली हजारों मछलियां, पकड़ने के लिए टूट पड़े लोग

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुरादाबाद।मुरादाबाद की रामगंगा नदी में हजारों मछलियां मृत पाई गई। इसकी जानकारी के बाद लोग उन्हें पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। बड़ी संख्या में मछलियां कैसे मरी इसकी बारे में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जिगर कॉलोनी के नजदीक रामगंगा नदी में शुक्रवार की सुबह बड़ी मछलियों को उतराई देख काफी संख्या में लोग ठंड की परवाह किए बगैर कूद पड़े। मछलियों को पकड़ने के बाद लोगों ने बताया कि बड़ी बेहोश हो गई और छोटी मछलियां मर गई हैं। आशंका है कि किसी ने नदी में कीटनाशक दवा डाल दी थी, जिसका प्रभाव मछलियों पर पड़ा है। जिगर कॉलोनी के लोग शुक्रवार की सुबह नदी में मछलियों को उतराया देखकर दंग रह गए। जिज्ञासा के चलते कुछ लोगों ने पानी से मछलियों को निकालना शुरू किया।

इनमें बड़ी मछलियां जिंदा थी लेकिन छोटी मछलियां मर गई थी। देखते ही देखते दर्जनों लोग मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। लोगों में मछली पकड़ने की होड़ मच गई। मुफ्त में मछलियों को पाकर लोग खुश हो गए।कुछ लोगों ने बड़ी मछलियों की बिक्री के लिए दुकानें सजा ली। लोगों की माने तो कई क्विंटल मछलियां नदी से निकाली गई हैं। इस बारे में पूछने पर जिला मत्स्य अधिकारी राजे लाल ने कहा कि नदी का क्षेत्र वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत है।

तालाब रहता तो वह निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं। इधर डीएफओ ने भी मछलियों के बारे में अनभिज्ञता जताई। लोगों का कहना है कि बहते हुए पानी में ऑक्सीजन की कमीं नहीं हो सकती है। आशंका है कि किसी ने नदी में कीटनाशक दवा फेंक दी है। इसी कारण मछलियां बेहोश हुई और छोटी मछलियों की मौत हो गई।

खतौनी में फर्जीवाड़ा कर दूसरे की एक बीघा दस बिस्वा जमीन अपनी मां के नाम करा ली

कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार में जमीन का खेल

» मामला सामने आने के बाद राजस्व अभिलेखपाल ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी के कलेक्ट्रेट परिसर से संचालित राजस्व अभिलेखागार में बड़ा खेल उजागर हुआ है। जमीन के सरकारी रिकॉर्ड, जिन्हें सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, वहीं से खतौनी में फर्जी नाम चढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अभिलेखागार कर्मियों की मदद से अपनी मां के नाम एक बीघा दस बिस्वा जमीन दर्ज करा ली, जबकि जमीन के असली खातेदार कोई और थे।

> राजस्व अभिलेखपाल की तहरीर पर आजम खां को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और रिकॉर्ड से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है।
>
> अश्विनी कुमार पांडेय
> नगर कोतवाल

मामला सामने आने के बाद खुद राजस्व अभिलेखपाल ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिससे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है। नगर कोतवाली के बौलिया जनौरा निवासी अशोक कुमार वर्मा, जो कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखपाल के पद पर तैनात हैं, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीकापुर तहसील के चौरे चंदौली, परगना पश्चिमी राठ क्षेत्र से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप था कि फसली वर्ष 1391 व 1396 की खतौनी में महिला बिट्टन पत्नी सगीर खां के नाम फर्जी तरीके से एक बीघा दस बिस्वा भूमि का नया खाता दर्ज कर दिया गया है।

जब प्रकरण की गहन जांच कराई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि के मूल खातेदार विक्रमा पुत्र सूर्यबक्श और ब्रह्मादीन पुत्र पाल हैं। इनके नाम दर्ज खतौनी में हेराफेरी कर अतिरिक्त खाता जोड़ दिया गया, जिसमें महिला बिट्टन का नाम दर्ज कर दिया गया। अभिलेखपाल के अनुसार यह फर्जीवाड़ा सुनियोजित तरीके से किया गया और इसका सीधा लाभ महिला बिट्टन के पुत्र आजम खां को मिलना था। इस प्रकरण ने कलेक्ट्रेट के भीतर चल रही कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिना अंदरूनी मिलीभगत के खतौनी में नया खाता जोड़ा जा सकता है? किसके संरक्षण में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई? क्या ऐसे और भी फर्जी नाम जमीनों में दर्ज किए गए हैं? सूत्रों की मानें तो यह मामला सिर्फ एक उदाहरण हो सकता है, जिसकी परतें खुलनी अभी बाकी हैं।

अयोध्या में सफाई व्यवस्था ठप कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे

2200 सफाई कर्मचारी अनिश्तिकालीन हड़ताल पर चले गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नगर निगम के करीब 2200 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी शुक्रवार देर शाम से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कर्मचारियों का आरोप है कि नवनियुक्त ठेकेदार द्वारा कार्यस्थलों पर मनमानी की जा रही है। वेतन में कटौती, भुगतान में देरी और कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम परिसर में एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हुई आम सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बाघमार, प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान के लिए दबाव बनाया जाएगा।

सभा के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार की अमानवीय कार्यशैली और दबाव के चलते काम करना मुश्किल हो गया है। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

हड़ताल के चलते सुबह से ही शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में गंदगी बढ़ती दिखी। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक ठेकेदार की मनमानी पर रोक नहीं लगती और वेतन व कार्यस्थितियों में सुधार नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी नेता विजय बाघमार ने कहा कि ठेकेदार की मनमानी अब असहनीय हो चुकी है और यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उधर, नगर निगम प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव पत्नी के फोन में 210 मिस कॉल

» गुरुवार को तारुन थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। कोतवाली क्षेत्र के मणि पर्वत स्थित जिन्नादी मस्जिद के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनुराग वर्मा (20) निवासी परसावां मोहल्ला, थाना तारुन के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों ने सुबह मस्जिद की ओर जाते समय शव देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बुलवाकर शव नीचे उतरवाया। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसकी जेब से मोबाइल फोन मिला, जिसमें 210 से अधिक मिस कॉल दर्ज थीं। उसी दौरान फोन पर कॉल भी आ रही थी, जिसे उसकी पत्नी काजल का बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार अनुराग ने करीब एक वर्ष पूर्व विवाह किया था। वह पत्नी के साथ दर्शननगर में किराए के मकान में रहता था और हलवाई का काम करता था।

पत्नी काजल ने बताया कि मंगलवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अनुराग घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद गुरुवार को तारुन थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोतवाली प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शरीर की स्थिति से अनुमान है कि युवक ने बुधवार देर रात फांसी लगाई होगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

24 साल पहले आतंकियों ने बनाया था लोकतंत्र के मंदिर को निशाना

प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी सहित कई सांसदों ने किया शहीदों को नमन

आतंकी हमले को आज 24 साल पूरे

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। 13 दिसंबर 2001 के दिन ही संसद पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले को आज 24 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जिनमें दिल्ली पुलिस के 6 पुलिसकर्मी और संसद के 2 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इसके अलावा संसद में काम करने वाला एक माली भी इस आतंकी हमले में मारा गया था। संसद आतंकी हमले की 24वीं बरसी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कौन था आतंकी हमले का मास्टरमाइंड?

संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था, जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। जैश के 5 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिन्हें सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रजा और मोहम्मद के रूप में हुई थी। इस आतंकी हमले में 18 लोग घायल भी हुए थे।

भारत-पाकिस्तान में हुआ था सैन्य गतिरोध

इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस वजह से 2001-2002 में भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र में बॉर्डर के दोनों ओर और एलओसी पर सैन्य गतिरोध हुआ था , जो 13 दिसंबर 2001 से 10 जून 2002 तक चला था। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पराक्रम नाम दिया था। इस गतिरोध को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रोका गया। भारत के सैकड़ों सैनिक इस सैन्य गतिरोध में शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की तुलना में ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था।

लालू यादव की संपत्ति होगी जब्त, खोले जाएंगे स्कूल

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

पटना। बिहार की भाजपा सरकार जल्द ही पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करने वाली है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि लालू की संपत्ति को सीज करके वहां पर बच्चों के स्कूल शुरू किए जाएंगे। मीडिया बातचीत के दौरान चौधरी ने यह बयान देते हुए चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी भी बताया।

950 करोड़ के चारा घोटाले का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा, सीबीआई और ईडी द्वारा लालू की संपत्तियों को अटैच किया गया था। इसी में संजय गांधी जैविक उद्यान के पास मौजूद एक बिल्डिंग भी शामिल है, जो करीब 20 साल से बंद है। चौधरी ने कहा कि इस बिल्डिंग का ताला खोल कर अब इसमें बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा।

इसके लिए बिल्डिंग की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराई जाएगी और फिर स्कूल शुरू किया जाएगा। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, इस बिल्डिंग में स्कूल खुलेगा तो लालू यादव को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी। चौधरी ने आगे कहा, जिन लोगों ने अपराध करके पैसा और प्रोपर्टी जमा किए है उन्हें सरकार जब्त करेगी और उनसे स्कूल जरूर खोलेगी। चौधरी ने कहा, लालू यादव रजिस्टर्ड अपराधी हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, सब एक न एक दिन जेल जाएंगे और उन्हें अपनी अवैध संपत्तियों को सरकार को सौंपना होगा।

दिल्ली में क्रिसमस-न्यू ईयर पर अब नहीं फूटेंगे पटाखे

गोवा हादसे के बाद रेखा सरकार का बड़ा फैसला

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने को है। राजधानी दिल्ली नए साल का जश्न मनाने को तैयार है। क्रिसमस की रौनक और न्यू ईयर की धूम के लिए दिल्ली के क्लब, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इस बार पार्टी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इन जगहों पर पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही है। गोवा के नाइट क्लब में हुए खौफनाक हादसे के बाद ये फैसला लिया गया।

हाल ही में गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने सबको हिला कर रख दिया। इस दर्दनाक घटना ने सभी की आंखें खोलकर रख दी हैं। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के आबकारी विभाग ने फैसला लिया है कि पार्टी की मस्ती में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

क्लब और रेस्टोरेंट वालों को सख्त हिदायत

10 दिसंबर को जारी आदेश में विभाग ने सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (एचसीआर) लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है। फायर एनओसी हमेशा वैलिड रखें। फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह चालू हालत में हों। इसके अलावा परिसर में किसी भी तरह के पटाखे चाहे पारंपरिक हों या इलेक्ट्रिक पूरी तरह बैन हैं। अगर कोई गलती हुई तो दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और नियम 2010 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल तक हो सकता है।

शहर में करीब 950 रेस्टोरेंट, बार और क्लब आबकारी विभाग के साथ रजिस्टर्ड हैं। खास बात ये कि 90 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा एरिया वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपना फायर एनओसी समय पर रिन्यू कराना अनिवार्य है।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से यूपी को मिलेगी नई शक्ति

35 हजार करोड़ के निवेश से 52 हजार नौकरियां

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से जमीन पर उतर रहा है। कॉरिडोर में अब तक 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनसे 11,997.45 करोड़ रुपये का निवेश और 14,256 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके साथ ही 110 और कंपनियों के साथ एमओयू पाइपलाइन में हैं। सरकार का दावा है कि 197 एमओयू से 35 हजार करोड़ निवेश के साथ 52,658 नौकरियों का अनुमान है। इस क्षेत्र की ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका है।

यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने कॉरिडोर के 6 नोड्स अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा में 2,097 हेक्टेयर भूमि को मंजूरी दी है। इसमें से 2,040 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है।वर्तमान में 1,598.92 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। अलीगढ़ में सबसे अधिक 24 कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है, जबकि कानपुर में 5 कंपनियों को 210 हेक्टेयर और सबसे अधिक क्षेत्रफल झांसी में 17 कंपनियों

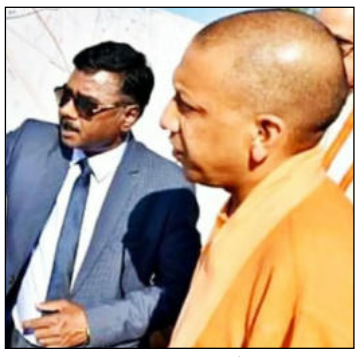

को 571 हेक्टेयर दिया गया है। लखनऊ में 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से अधिक भूमि देने के साथ और चित्रकूट, अलीगढ़ फेज-2 और आगरा में भी जल्द भूमि आवंटन शुरू होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय मॉनिटरिंग में डिफेंस कॉरिडोर के लिए कुल 197 एमओयू साइन हो चुके हैं, जिनमें 172 औद्योगिक एमओयू शामिल हैं। इनसे 34,844.49 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश और 52,658 रोजगार सृजन का अनुमान है। अगले चरण में 110 से अधिक प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों से 22,847 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 38,000 से अधिक रोजगार की संभावना है।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न सिर्फ यूपी में भारी निवेश आकर्षित कर रहा है, बल्कि उच्च तकनीक आधारित रोजगार और उद्योगों के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

गुजरात व तमिलनाडु को टक्कर दे रहा यूपी

यूपीडा के एसीईओ एचपी. शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप कॉरिडोर तेजी से उभर रहा है। इसे एक जिला-एक उत्पाद और मेक इन इंडिया मिशन के साथ जोड़कर विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ नोड में स्थापित ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट है, जिसकी वजह से यूपी का रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। आज यूपी रक्षा उत्पादन में तेजी से अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक रक्षा विनिर्माण केंद्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। आने वाले महीनों में कई नई बड़ी घोषणाओं के साथ भारत के रक्षा इकोसिस्टम में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है।